प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतीन्कर दीवाकर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3504/2009

याचिकाकर्ता रवींद्र सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3538/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता प्रतीक्षा पाण्डे

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

आदेश उद्घोषित करने हेतु दिनांक 18.10.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

प्रीतीन्कर दीवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतीन्कर दीवाकर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3504/2009

याचिकाकर्ता रवींद्र सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल और श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 से 6 की ओर से श्री मतीन सिद्दीकी, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3538/2009

याचिकाकर्ता प्रतीक्षा पाण्डे

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल और श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 से 6 की ओर से श्री मतीन सिद्दीकी, अधिवक्ता।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

आदेश

(18.10.2011)

इन दोनों याचिकाओं में सम्मिलित तथ्य बिल्कुल समान होने के कारण, इन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जाता है।

इन दोनों रिट याचिकाओं में विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के आक्षेपित परिणाम को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 3.11.2008 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा विज्ञापन क्र. 09/2008 प्रकाशित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा नियमों के नियम 1 (जिसे सुविधा के लिए आगे "परीक्षा नियम" कहा जाएगा) के तहत निर्धारित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, विभिन्न अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म भरे और प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया, जो दिनांक 1.2.2009 को आयोजित की गई थी। याचिकर्ताओं का आगे यह कथन है कि वे विधि के अनुसार, परीक्षा नियमों के नियम 3 (1) का पालन न किए जाने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहे। उनके अनुसार, लोक सेवा आयोग पर परीक्षा नियमों के नियम 3 (1) के अनुसार प्रत्येक श्रेणी अर्थात् (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए पृथक सूचियाँ तैयार करने का दायित्व था, लेकिन वर्तमान प्रकरण में आयोग ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों अर्थात् (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) को अनारक्षित श्रेणी की सूची में शामिल करके त्रुटि की है। उनका आगे यह कहना है कि यदि अनारक्षित श्रेणी की सूची में अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया होता, तो शायद याचिकाकर्ताओं को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया होता। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के कुल 1,246 अभ्यर्थियों (177 अनुसूचित जाति, 155 अनुसूचित जनजाति और 914 अन्य पिछड़ा वर्ग) को शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने अर्हक अंक प्राप्त किए हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षा नियमों का नियम 3 (1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान नहीं करता है, और उक्त परीक्षा नियमों के तहत यह समावेशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परीक्षा नियमों का नियम 3 (iii) (ख) अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में केवल अंतिम चयन के चरण में शामिल करने का प्रावधान करता है, न कि प्रारंभिक परीक्षा के चरण में। उनके अनुसार, परीक्षा नियमों

का उप-नियम 3 (i) (घ) केवल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, और इसलिए लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने की कार्यवाही विधि के अनुरूप नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और उस स्तर पर किसी भी श्रेणी के तहत कोई आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब प्रारंभिक परीक्षा के समय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है, तो नियमों का सीधा निर्वचन किया जाना और लोक सेवा आयोग परीक्षा नियमों के नियम 3 (iii) (ख) का कोई लाभ नहीं ले सकता है, जो वास्तव में मुख्य परीक्षा के लिए है। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पिछली परीक्षाओं में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा नियमों का अलग निर्वचन किया था और प्रारंभिक परीक्षा के समय श्रेणीवार एक अलग सूची तैयार की गई थी, जिसमें उक्त परिणाम घोषित करते समय आरक्षित श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। उनके अनुसार, चूंकि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और उक्त परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस चरण में कोई आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष 2003 में भी लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित की थी जिसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, और यह तथ्य अनुलग्नक पी-5 से स्पष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्कों का जवाब देते हुए, उत्तरवादी/लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क दिया है कि नियमों का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए और यदि संपूर्ण नियम 3 को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) के एक उच्च अंक लाने वाले अभ्यर्थी को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सूची में शामिल होने का पूरा अधिकार है। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि परीक्षा नियमों का नियम 3 (iii) (ख) स्थिति को स्पष्ट करता है, जहां विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आरक्षित श्रेणी में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सूची में शामिल किया जाएगा और उसके बाद विभिन्न श्रेणियों के लिए एक पृथक सूची तैयार की जाएगी। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि परीक्षा नियमों के नियम 3 (iii) (ख) में विधायी व्यादेश यह है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी, उसके/उसकी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान पाता है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में दर्शाया जाएगा और उसे आरक्षित रिक्तियों में नहीं गिना जाएगा। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नियम 3 (i) को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है और पूरे नियम

को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, जब तक लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मनमाना या निष्पक्षता के ज्ञात सिद्धांत के विरुद्ध नहीं माना जाता है, तब तक सामान्य तौर पर यह न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। श्री अग्रवाल के अनुसार, जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अनुचित या मनमानी है, तब तक न्यायालयों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह तर्क दिया जाता है कि अनारक्षित श्रेणी में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, भले ही वे किसी भी जाति या समुदाय से संबंधित हों। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने (1995) 2 SCC 745 में प्रकाशित आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1995) 6 SCC 684 में प्रकाशित भारत संघ और अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान और अन्य, (1996) 3 SCC 253 में प्रकाशित रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यमूल और अन्य , (2006) 4 SCC 550 में प्रकाशित भारत संघ और अन्य बनाम सत्य प्रकाश और अन्य, (2009) 4 SCC 1 में प्रकाशित बिहारी लाल राडा बनाम अनिल जैन (टीनू) और अन्य और (2009) 5 SCC 1 में प्रकाशित आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बालोजी बधावथ और अन्य के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य के अधिवक्ता ने लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए रुख को अपनाते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार की कार्यवाही विधि के अनुरुप है और उसमें कोई दुर्बलता नहीं है। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 12.5.2009 के परिपत्र में राज्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभ में "सामान्य श्रेणी" शब्द का उपयोग किया गया था, लेकिन अनुलग्नक आर-2 के माध्यम से "सामान्य" शब्द को "अनारक्षित" से बदल दिया गया है, और शाब्दिक अर्थ के अनुसार "अनारक्षित" शब्द में अन्य श्रेणियां भी शामिल हैं।

6. उत्तरवादी क्रमांक 3 से 6 के अधिवक्ता ने भी उत्तरवादी क्रमांक 2/लोक सेवा आयोग के तर्कों को अपनाते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने काल्पनिक स्थिति के आधार पर तथा इस धारणा पर याचिका दायर की है कि अनारक्षित श्रेणी के तहत विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शामिल करने के कारण, याचिकाकर्ता प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो सके, जबकि उन्होंने विनिर्दिष्ट अभिवचनों के माध्यम से अपने प्रकरण को सिद्ध नहीं किया है। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में भाग ले लिया है, तो उसमें असफल होने के कारण उन्हें परीक्षा की प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. यह विधि की स्थापित स्थिति है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की सूची में अपना नाम शामिल करवाने का पूरा अधिकार है, परंतु कि उनकी आरक्षित श्रेणी में सराहनीय स्थिति हो। केवल उनकी जाति और समुदाय के आधार पर, उनके नाम अनारक्षित श्रेणी की सूची से बाहर नहीं किए जा सकते।

आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, जो (1995) 2 SCC 745 में प्रकाशित हुआ है, के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

> "4. जब किसी विशेष कैडर के संबंध में आरक्षण का एक प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और रोस्टर आरक्षित बिंदुओं को इंगित करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि आरक्षित बिंदुओं पर दर्शाये गए पद आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों में से भरे जाने हैं और सामान्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में, उनकी संख्या को आरक्षण के प्रतिशत की गणना के लिए जोड़ा और ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य सरकार को यह अनुमति है कि वह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित कोई प्रावधान कर सके, यदि राज्य की राय में वह वर्ग पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस पिछड़े वर्ग/वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है, वे राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसा करते समय राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या तथा राज्य सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख सकती है। जब राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के बाद आरक्षण लागू करती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों के प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है, तो उस प्रतिशत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रतिशत को केवल इसलिए अलग या बदला नहीं जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के विरुद्ध नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु को उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। रोस्टर में उस स्लॉट के विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। यह तथ्य कि पिछड़े वर्ग के बड़ी संख्या में सदस्यों को राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के विरुद्ध नियुक्त/पदोन्नत किया गया है, राज्य सरकार के लिए उक्त वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा करने हेतु एक सुसंगत कारक हो सकता है, लेकिन जब तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान करने वाले निर्देश/नियम लागू हैं, तब तक उनका पालन किया जाना चाहिए। सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी संख्या में नियुक्तियों/पदोन्नत व्यक्तियों के बावजूद, दिए गए प्रतिशत को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पहले तर्क में कोई बल नहीं देखते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं।"

भारत संघ और अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान और अन्य, जो (1995) 6 SCC 684 में प्रकाशित हुआ है, के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

29"....(i) एक बार जब किसी कैडर, श्रेणी या ग्रेड (आरक्षण नियम लागू करने के लिए इकाई) में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित पदों की संख्या रोस्टर के संचालन से भर जाती है, तो आरक्षण के नियम का उद्देश्य प्राप्त माना जाना चाहिए और उसके बाद रोस्टर का पालन **आर.के. सभरवाल** के कंडिका-5 में इंगित सीमा तक के अलावा नहीं किया जा सकता है। उक्त संख्या का निर्धारण करते समय, आरक्षित श्रेणी से संबंधित वे अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर (और आरक्षण के नियम के आधार पर नहीं) चुने/पदोन्नत हुए हैं, उन्हें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में नहीं गिना जाएगा.. ..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, **रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यमूल और अन्य, जो (1996) 3 SCC 253** में प्रकाशित हुआ है, के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

14. इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(1992 सप. (3) सुप्रीम कोर्ट केसेस 217] में, जिसे सामान्यतः मंडल केसेस के रूप में जाना जाता है, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:- (एससीसी पृष्ठ 735, कंडिका 811)

"इस संबंध में यह याद रखना ज़रूरी है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण सामुदायिक आरक्षण की तरह कार्य नहीं करते हैं। यह आसानी से हो सकता है कि, उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में चुने जाते हैं; उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए

आरक्षित कोटे के विरुद्ध नहीं गिना जाएगा; उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के अभ्यर्थी माना जाएगा।"

15. आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य **[(1995) 2** सुप्रीम कोर्ट केस, **745]** में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने नियुक्ति और पदोन्नति तथा रोस्टर बिंदुओं के संदर्भ में आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:- **(**एससीसी पृष्ठ **750,** कंडिका **4)**

"जब किसी विशेष कैडर के संबंध में आरक्षण का एक प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और रोस्टर आरक्षित बिंदुओं को इंगित करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि आरक्षित बिंदुओं पर दर्शाये गए पद आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों में से भरे जाने हैं और सामान्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में, उनकी संख्या को आरक्षण के प्रतिशत की गणना के लिए जोड़ा और ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद **16(4)** राज्य सरकार को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान के निर्माण की अनुमति देता है, जिसका, राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए यह निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवार्य है कि जिस पिछड़े वर्ग/वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है, उसका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा करते समय, राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या और राज्य सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व को ले सकती है। जब राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के बाद आरक्षण लागू करती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों के प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है, तो उस प्रतिशत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रतिशत को केवल इसलिए अलग या बदला नहीं जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के विरुद्ध नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है।"

"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु को उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। रोस्टर में उस स्लॉट के विरुद्ध किसी भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। यह तथ्य कि पिछड़े वर्ग के बड़ी संख्या में सदस्यों को राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के विरुद्ध नियुक्त/पदोन्नत किया गया है, राज्य सरकार के लिए उक्त वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा करने हेतु एक सुसंगत कारक हो सकता है,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेकिन जब तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के एक निश्चित प्रतिशत का प्रावधान करने वाले निर्देश/नियम लागू हैं, तब तक उनका पालन किया जाना चाहिए। सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी संख्या में नियुक्तियों/पदोन्नत व्यक्तियों के बावजूद, दिए गए प्रतिशत को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।"

16. भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान **[(1995) 6** एससीसी **684 705]** के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या निर्धारित करते समय, आरक्षित श्रेणी से संबंधित वे अभ्यर्थी जिन्हें योग्यता के नियम पर (और आरक्षण के नियम के आधार पर नहीं) चयनित/पदोन्नत किया गया है, उन्हें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में नहीं गिना जाएगा।

17. अजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, **[(1994) 4** एससीसी **401]** के प्रकरण में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इसी प्रश्न पर विचार किया। यह तर्क दिया गया था कि एक बार जब स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों ने अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के चरण पर आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो वे आरक्षित अभ्यर्थियों के रूप में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। यह तर्क कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के चरण पर आरक्षण का प्रावधान अनावश्यक है और सार्वजनिक हित के विपरीत है, स्वीकार नहीं की जा सकती। सबसे पहले, जिस धारणा के आधार पर यह तर्क दिया गया है, वह असमर्थनीय है। एक अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के चरण पर आरक्षण चाहता है, उसने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के चरण पर आरक्षण का लाभ नहीं लिया होगा चूंकि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के स्तर पर प्रतिस्पर्धा अत्यधिक तीव्र है, इसलिए उसे आरक्षण का लाभ लेना पड़ सकता है। इसलिए, यह धारणा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के चरण पर आरक्षण का लाभ चाहने वाले छात्र ने पहले ही एक बार आरक्षण का लाभ उठा लिया है, आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। दूसरे, अनुच्छेद **15 [4]** के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी छात्र को उसके शैक्षिक करियर के दौरान एक से अधिक चरणों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। सीमा कहाँ खींची जाए यह विध का मामला नहीं है, बल्कि समाज के बड़े हितों और विभिन्न अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए विकसित की जाने वाली नीति का प्रकरण है। जब तक राज्य द्वारा खींची गई रेखा को संबंधित अनुच्छेद के तहत पोषणीय नहीं पाया जाता है, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इंदिरा साहनी प्रकरण में कंडिका 834 और 839 में किए गए उन अवलोकनों के संबंध में, जिन पर यह तर्क देने के लिए अवलंब लिया गया था

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आरक्षण असंवैधानिक है, कंडिका 8 में यह स्पष्ट किया गया था कि "न्यायालय विशेषज्ञता और उच्च विशेषज्ञताओं में प्रवेश की बात नहीं कर रहा था, इसके अलावा, एमएस या एमडी उच्च विशेषज्ञता नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय ने यह नहीं कहा कि वे स्वीकार्य नहीं थे"। यह तर्क कि स्नातकोत्तर स्तर पर आरक्षण समाज के हितों के लिए हानिकारक है, को यह मानते हुए स्वीकार नहीं किया गया कि "किसी को भी तब तक उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपेक्षित स्तर की प्रवीणत प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे, शैक्षणिक प्रदर्शन अभ्यास में दक्षता की गारंटी नहीं है। हमने विधि और चिकित्सा दोनों में देखा है कि अच्छा शैक्षणिक इतिहास वाले व्यक्ति प्रदर्शन में सफल नहीं होते हैं, जबकि जो छात्र कम बुद्धिमान माने जाते थे, वे व्यवसाय/अभ्यास में सफल होते हैं। इसलिए, यह मान लेना गलत है कि अच्छा शैक्षणिक इतिहास वाला चिकित्सक अभ्यास में बेहतर चिकित्सक साबित होगा। ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है"। उपरोक्त प्रकरणों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक स्थिति के दृष्टिगत, यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि एक छात्र जो योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने का हकदार है, भले ही वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित हो, उसे आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के विरुद्ध भर्ती हुआ नहीं माना जा सकता। लेकिन साथ ही, प्रावधान इस तरह से किए जाने चाहिए कि यह ऐसे अभ्यर्थी के हानि के रूप में कार्य न करे और उसे अन्य कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अलाभकारी स्थिति में न रखा जाए। उपरोक्त उद्देश्य तब प्राप्त किया जा सकता है जब आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों का पता लगाने के बाद जो अन्यथा सामान्य मेरिट सूची में आएंगे, उनसे उन विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उनका विकल्प पूछा जाए जो आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं, और उसके बाद कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रकरणों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें उन महाविद्यालयों में सीटें आवंटित की जानी चाहिए जिनमें सीटें उपलब्ध हों। दूसरे शब्दों में, जबकि योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए हकदार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के पास उन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहाँ आरक्षित श्रेणी के लिए एक निर्दिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित रखी गई हैं, लेकिन आरक्षण के प्रतिशत की गणना करते समय, उसे एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भर्ती हुआ माना जाएगा न कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अश्विन प्रफुल्ल पिंपलवार बनाम महाराष्ट्र राज्य के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे या उसके नियंत्रण के अधीन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन, शासन द्वारा अधिसूचित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के चयन के नियम में निहित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उस संबंध में निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। यह तर्क कि पिछड़े वर्गों से संबंधित वे अभ्यर्थी जिन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, वे आरक्षित अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश या छात्रवृत्ति आदि के लिए और आरक्षित अभ्यर्थियों के रूप में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी पात्र नहीं हैं, अवैध है और अनुच्छेद **15(4)** का उल्लंघन है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए कथन के आधार पर सरकार द्वारा जारी ज्ञापन हमारे सामने रखा गया था, जिसमें दर्शाया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर भर्ती होने के बावजूद सभी हितों के हकदार हैं। उक्त कथन अनुच्छेद **15(4)** के अनुरूप है। इसलिए, पिछड़े वर्गों से संबंधित लेकिन स्नातक या स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में चयनित अभ्यर्थी, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियमों या निर्देशों के अनुसार छूट या छात्रवृत्तियों और अन्य हितों के हकदार हैं। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष **1995-96** के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पहले ही हो चुका है और हम पहले से किए गए प्रवेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हम यह सिफारिश करते हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए नियमों का निर्णय और प्रकाशन करते समय इस निर्णय में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखा जाए और नियम तदनुसार बनाए जाएं। हमारे निष्कर्ष के दृष्टिगत, और यह मानते हुए कि अधिकारियों ने आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को केवल आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों के विरुद्ध ही भर्ती किया, भले ही वे अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार थे, याचिकाकर्ता, जिसे अन्यथा प्रवेश दिया जा सकता था, को प्रवेश लेने से विवर्जित किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता हमारे सामने एकल आवेदक है, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाए जहां उसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भर्ती किया जा सकता है, जहां सीट अभी भी उपलब्ध है और यदि कोई सीट उपलब्ध नहीं है तो उसे किसी भी महाविद्यालय में एक सीट बढ़ाकर प्रवेश दिया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पाने का इच्छुक है, तो उसे आज से दो सप्ताह के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी उसके बाद दो सप्ताह के भीतर उचित कार्यवाही करेगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी उस महाविद्यालय का निर्णय करेगा जिसमें याचिकाकर्ता को भर्ती किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत संघ और एक अन्य बनाम सत्य प्रकाश और अन्य, जो (2006) 4 SCC 550 में प्रकाशित हुआ है, के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

18. उदाहरण के तौर पर, एक आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा शिथिल मानक का आश्रय लिए बिना (अर्थात् योग्यता के आधार पर) अनुशंसित किया गया है, उसे

मेरिट/सामान्य श्रेणी में अपनी पसंदीदा सेवा 'उदाहरण के लिए आईएएस' नहीं मिली। उसके लिए, वह आरक्षित श्रेणी से एक वरीयता चुन सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने आरक्षित श्रेणी से एक वरीयता चुनी है, वह शिथिल मानक के तहत चयनित अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी के कोटे को समाप्त नहीं करता है। अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई ऐसी वरीयता, जिसे आयोग द्वारा शिथिल मानक का आश्रय लिए बिना (अर्थात् योग्यता के आधार पर) अनुशंसित किया गया है, को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। यह नियम **16** के उप-नियम **2** के परंतुक का अधिदेश है।**19.** दूसरे शब्दों में, जबकि एक आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा शिथिल मानक का आश्रय लिए बिना अनुशंसित किया गया है, के पास आरक्षित श्रेणी से वरीयता का विकल्प होगा, जिसे आयोग द्वारा शिथिल मानक का आश्रय लेकर अनुशंसित किया गया है, लेकिन आरक्षण के कोटे/प्रतिशत की गणना करते समय, उसे एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में (अर्थात् योग्यता के आधार पर) सीट आवंटित किया गया माना जाएगा और आयोग द्वारा शिथिल मानक का आश्रय लेकर अनुशंसित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में नहीं माना जाएगा।

20. यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा शिथिल मानक का आश्रय लिए बिना अनुशंसित किया गया है, मेरिट सूची में अपनी पसंदीदा सेवा नहीं प्राप्त कर सका, तो वह आरक्षित श्रेणी से एक वरीयता चुन सकता है और ऐसी प्रक्रिया में, शिथिल मानक का आश्रय लेकर अनुशंसित आरक्षित श्रेणी की वरीयता का चयन और आगे नीचे धकेल दिया जाएगा, लेकिन उसे शेष सेवाओं/पदों में से किसी में भी आवंटित किया जाएगा जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों के आवंटन के बाद रिक्तियां हैं जिन्हें उनकी वरीयता के अनुसार किसी सेवा/पद पर आवंटित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, **बिहारी लाल राडा बनाम अनिल जैन (टीनू) और अन्य, जो (2009) 4 SCC 1** में प्रकाशित हुआ है, के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

32. 1973 का अधिनियम, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के माध्यम से सीटों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को उनकी अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित सीटों से चयनित होने से नहीं रोकता है। ऐसे आरक्षण का स्पष्ट उद्देश्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को, जिन्हें आरक्षण के अभाव में स्थानीय निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था, उन्हें आरक्षण प्रदान करना है। आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम न्यूनतम संख्या में ऐसे वर्गों से संबंधित व्यक्ति चयनित होंगे। उनके

पक्ष में किए गए आरक्षण का यह तात्पर्य नहीं है कि वे अनारक्षित सीटों और यथास्थिति, अध्यक्ष के पदों से चुनाव लड़ने के हकदार नहीं हैं। आरक्षण आरक्षित श्रेणी से चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित नहीं करता है। वे अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़ने और चयन होने के पात्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता है।

40. चाहे जो भी हो, न तो संविधान का अनुच्छेद 243- न और न ही हरियाणा नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 (5) किसी ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में अध्यक्ष के पद के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान करती है जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। स्पष्ट है कि नगर पालिकाओं में सीटों के लिए और न ही अध्यक्ष के पद के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐसा कोई आरक्षण हो सकता है। सामान्य श्रेणी जैसी कोई पृथक श्रेणी नहीं है। 'सामान्य श्रेणी से संबंधित' अभिव्यक्ति, जहाँ कहीं भी उपयोग की जाती है, उसका अर्थ उन सीटों या कार्यालयों से है जो सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, भले ही वे उनकी जाति, वर्ग, समुदाय या जनजाति के हों। अनारक्षित सीटों को जो संकेतात्मक रूप से सामान्य श्रेणी की सीटें वर्णित किया गया है, वे सभी अभ्यर्थियों के लिए खुले पद हैं जो अन्यथा उस कार्यालय के लिए निर्वाचित होने हेतु योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. 1973 के अधिनियम के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि यदि किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के पद को सामान्य श्रेणी के सदस्यों में से भरा जाना आवश्यक है, तो केवल एक ऐसा सदस्य ही चुनाव लड़ सकता है जो अनारक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ हो। विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्ति, जो उस वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है, अध्यक्ष/सभापति के पद के लिए चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए, जबकि वह पद आरक्षित नहीं है और सामान्य श्रेणी के सदस्यों में से भरा जाना है।

43. हमारी राय में, जहाँ भी किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का पद, यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्य द्वारा भरा जाना आवश्यक है, तो यह पर्याप्त होगा कि वह उन श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हो, भले ही वह इस तथ्य से अप्रभावित हो कि वे एक सामान्य वार्ड या आरक्षित वार्ड से निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार, यदि किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं है या सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित है, तो सभी अभ्यर्थी, उनकी जाति, वर्ग या समुदाय से अप्रभावित होकर और इस तथ्य से भी अप्रभावित होकर कि वे एक आरक्षित वार्ड या एक सामान्य वार्ड से

निर्वाचित हुए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने और प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हैं।

9. याचिकाकर्ताओं ने उन नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी है जिनके आधार पर चयन किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का यह प्रकरण नहीं है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी है या निष्पक्षता के ज्ञात सिद्धांत के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं के अभिवचनों से यह परिलक्षित नहीं होता है कि उन्होंने इस आशय का कोई ऐसा आरोप अधिरोपित किया है जिससे वे अपना मामला सिद्ध कर सकें। **आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बालोजी बधावथ और अन्य, जो (2009) 5 SCC 1** में प्रकाशित हुआ है, के प्रकरण में लगभग समान प्रश्न का निराकरण करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

> 25. आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन कैसे करेगा, यह उसका कार्य है। जब तक उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मनमाना या निष्पक्षता के ज्ञात सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं माना जाता है, तब तक उच्च न्यायालय आमतौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य ने एस. जफीर साहब (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में नियम बनाए। अपने आप में, इसने कोई अवैधता नहीं की। उक्त निर्णय की शुद्धता, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अंतिम रूप प्राप्त कर लेने के कारण प्रश्न में नहीं है। हालाँकि, मामला पृथक होगा यदि उक्त नियम अपने आप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में किसी को भी नियुक्त होने का कोई मूल अधिकार नहीं है। यह केवल उस पर विचार किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे अधिकार पर विचार करने के लिए मोड और तरीका निर्धारित करने हेतु विकसित की गई प्रक्रिया में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब वह मनमानी, भेदभावपूर्ण या पूरी तरह से अनुचित हो।
>
> 32. योग्यता का आकलन कई स्तरों पर हो सकता है। इसे कई स्तर की छानने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अंततः, संवैधानिक योजना का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को प्राप्त करना है जो समाज की सेवा करने और पद से जुड़े कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों। रिक्तियों को दान के रूप में नहीं भरा जाता है। हर श्रेणी में अभ्यर्थियों और/या छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर चुनने पर बार-बार ज़ोर दिया गया है। वंचित समूह या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग खुली श्रेणी के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि वे इसके लिए निर्धारित न्यूनतम मूलभूत मानदंड को पारित करने में सक्षम नहीं होंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

34. श्री राव का यह तर्क कि ऐसी प्रक्रिया के कारण, पिछड़े वर्गों के केवल अग्र वर्ग को ही वरीयता दी जाएगी, जिन्हें कोचिंग कक्षाओं आदि में भाग लेने का लाभ प्राप्त है, शायद सही न हो। उच्च न्यायालय के समक्ष या हमारे समक्ष कोई सांख्यिकीय आंकडे प्रस्तुत नहीं किया गया था। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस तरह का तर्क किस आधार पर उठाया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी अत्यधिक शिक्षित हैं। योग्यता केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एकाधिकार नहीं है। राज्य को कुछ मानदंड अपनाने होंगे। अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए, यह लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा में और साथ ही साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दे सकता। यह अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए प्रक्रिया तैयार करने हेतु बाध्य है।

35. आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियमों का नियम 4, जो आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों, 1996 के नियम 22 और 22-क को संदर्भित करता है, केवल वहीं लागू होगा जहाँ चयन प्रक्रिया की जाती है। उक्त नियम का पहला भाग आयोग को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को उस सीमा तक सीमित करने का अधिकार देता है जितना वह उचित समझे। हालांकि, चयन करते समय, यह एक लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है या एक वरीयतात्मक या उच्च योग्यता और अनुभव का प्रावधान कर सकता है और केवल उस उद्देश्य के लिए इसे आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 22 और 22क के संदर्भ में आवश्यकताओं और स्थानीय अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण के नियम को ध्यान में रखना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. श्री राव ने संग्राम सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल, कोटा, भूरे लाल बाया [(1955) 2 एस सी आर 1] के मामले का अवलंब लिया है, जिसमें न्यायमूर्ति विवियन बोस ने निम्नानुसार कहा था:

16. "अब प्रक्रिया संहिता को वैसा ही माना जाना चाहिए। यह एक 'प्रक्रिया' है, जिसे न्याय को सुगम बनाने और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए गढा गया है: यह दंड और शास्तियों के लिए कोई दंडात्मक अधिनियमन नहीं है; यह लोगों को फंसाने के लिए नहीं बनाई गई है। इसलिए, धाराओं की ऐसी अत्यधिक तकनीकी व्याख्या जिससे व्याख्या की युक्तियुक्त लोच के लिए कोई जगह न बचे, उससे बचा जाना चाहिए (बशर्ते हमेशा 'दोनों पक्षकारों' के साथ न्याय किया जाए) ताकि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए गढे गये साधनों का उपयोग ही उसे विफल न कर दे।"

उक्त अवलोकन न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा का प्रावधान करने के कारण, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का अधिकार छीना नहीं गया है।

साधनों को उन लक्ष्यों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिन्हें संवैधानिक योजना प्राप्त करना चाहती है।

43. प्रकरण के एक अन्य पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि श्रेणी-वार विवरण तैयार किया जाता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, तो यह आरक्षित श्रेणियों से संबंधित मेधावी अभ्यर्थियों के हितों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होते हैं। यदि वे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मेधावी हैं, तो उन्हें उस श्रेणी में भर्ती किया जाता है। उनसे नीचे के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणियों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यह अब विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है। [देखें, उदाहरण के लिए, भारत संघ और अन्य बनाम सत्य प्रकाश और अन्य (2006) 4 एससीसी 550, कंडिका 18 से 20; रितेश आर. शाह बनाम डॉ. वाई.एल. यमूल (1996) 2; SCR 695 700-701, आर.के. दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, (2007) 8 SCC 785, कंडिका 9]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. 'सामान्य' शब्द लैटिन शब्द जीनस से लिया गया है। यह संपूर्ण प्रकार, वर्ग या क्रम से संबंधित है... यह प्रजाति या व्यक्ति को चिह्नित करने वाली चीज़ से अलग, जीनस या वर्ग से संबंधित या उसे नामित करने वाला है; सार्वभौमिक, विशेष के विपरीत गैर-विशेषीकृत; स्थानीय के विपरीत प्रमुख या केंद्रीय; चयनित के विपरीत सभी के लिए खुला या उपलब्ध; विशेष के विपरीत सामान्यतः प्राप्त या सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त; सीमित के विपरीत सार्वभौमिक या असीम; केवल एक भाग पर लागू होने या उसके लिए गढी गई किसी भी चीज़ से अलग, संपूर्ण को समाहित करने वाला या संपूर्ण की ओर निर्देशित। व्यापक या अनेकों में सामान्य।

शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "सामान्य" शब्द में किसी (विनिर्दिष्ट या निहित) संपूर्ण भाग, जैसे कि किसी क्षेत्र, समुदाय, संगठन आदि के सभी या लगभग सभी भागों को शामिल करना, उसमें सम्मिलित होना या उन्हें प्रभावित करना शामिल है; पूरी तरह से या लगभग सार्वभौमिक; आंशिक, विशेष, स्थानीय या खंडीय नहीं... सभी, सामूहिक, संपूर्ण। इन सबके अतिरिक्त, वेबस्टर के व्यापक शब्दकोश के अनुसार, "सामान्य" शब्द का अर्थ है अधिकांश लोगों में सामान्य या प्रचलित; आवेदन में प्रतिबंधित नहीं; विशेष वर्ग तक सीमित नहीं; विविध।

11. अब अगला प्रश्न यह तय करना है कि क्या परीक्षा नियमों के नियम 3 (1) को अकेले पढ़ा जाना है या यह प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, जबकि शेष नियम मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं। इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए, परीक्षा नियमों के संपूर्ण नियम 3 का संदर्भ लेना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

> 3. (i) प्रारंभिक परीक्षाओं में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों में से केवल लगभग उतने ही अभ्यर्थियों को, जो विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल पदों की संख्या के अधिकतम पंद्रह गुना के बराबर हैं, मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त माना जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तदनुसार घोषित किए जाएंगे। अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची अलग से तैयार की जाएगी और उनके परिणाम तदनुसार घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करेगी और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों पर अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के समय विचार नहीं किया जाएगा।
>
> (ii) मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले और आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों में से केवल लगभग उतने ही अभ्यर्थियों को, जो विभिन्न सेवाओं के तहत कुल पदों की संख्या के अधिकतम तीन गुना के बराबर हैं, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अर्हता प्राप्त माना जाएगा। इसी प्रकार, अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित, जो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अर्हता प्राप्त करते हैं, अभ्यर्थियों की एक अलग सूची तैयार की जाएगी।
>
> (iii) (a) साक्षात्कार के बाद, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में उन्हें दिए गए अंकों के कुल योग के आधार पर प्रकट हुई योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।
>
> किसी विशेष सेवा के लिए अभ्यर्थी की अनुशंसा करते समय, आवेदन में उसके/उसकी द्वारा व्यक्त की गई वरीयता पर, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उचित विचार किया जाएगा:
>
> (1). यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन में कोई वरीयता व्यक्त नहीं की है, तो विज्ञापन में इन पदों को जिस क्रम में सूचीबद्ध किया गया है, उसी क्रम में सभी पदों के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी वरीयता के किसी भी पद को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है, तो विज्ञापन में सूचीबद्ध किए गए क्रम में अन्य पद(दों) के लिए उसके कुल अंकों के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि, उसे किसी भी ऐसे पद(दों) के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि वह उस पर विचार नहीं किया जाना चाहता।

(3) 'पूरक सूची तैयार करते समय भी उपरोक्त सिद्धांत लागू होंगे।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रकरण में प्रत्येक पद के लिए मेरिट सूची आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक, इसी प्रकार अलग से तैयार की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित है और अपने कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान पाता है, तो उसे अनारक्षित सूची में दिखाया जाएगा और उसे आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध नहीं गिना जाएगा, इस शर्त के अधीन कि किसी भी समय, अनारक्षित सूची में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडा वर्ग के सदस्यों को शामिल करने के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, जिस पर चयन किया जा रहा है, श्रेणी II पद के प्रकरण में कुल पदों के 35% और श्रेणी III पद के प्रकरण में कुल पदों के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह इस अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा कि ऐसे अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई उत्तीर्ण अंकों में 10% तक की छूट के हकदार नहीं होंगे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त नियम के एक सामान्य पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि नियम का कुछ भाग केवल प्रारंभिक परीक्षा पर लागू होता है और कुछ भाग मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार पर। यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि नियम का सदैव सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाना चाहिए और व्याख्या सरल और सीधे अर्थ के आधार पर दी जानी चाहिए। यदि संपूर्ण नियम 3 को एक समग्र रूप में पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनारक्षित श्रेणी में सभी उच्च अंक लाने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे, भले ही वे उनकी श्रेणी (अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग) के हों। यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई बल नहीं पाता है कि परीक्षा नियमों का नियम 3 (iii) (ख) केवल मुख्य परीक्षा पर लागू होता है, बल्कि उक्त नियम यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न श्रेणियों के संबंध में मेरिट सूची कैसे तैयार की जाएगी।

13. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता है कि चूंकि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और उस परीक्षा के अंकों को मुख्य परीक्षा में नहीं गिना जाता है, इसलिए किसी भी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि यदि अभ्यर्थी उच्च अंक प्राप्त करने वाला है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी की सूची में शामिल होने का पूरा अधिकार है, भले ही वह परीक्षा प्रारंभिक हो या मुख्य, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी की सूची में उसका समावेशन योग्यता पर आधारित है, न कि किसी आरक्षण पर। अभ्यर्थी की योग्यता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को भी उन पर लागू आरक्षण के आधार पर अपनी संबंधित श्रेणी में शामिल होने का अधिकार है।

14. विचाराधीन प्रकरण में, याचिकाकर्ता विशिष्ट अभिवचन और साक्ष्य के समर्थन से यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की सूची में शामिल करने के कारण उन्हें कैसे कोई पूर्वाग्रह हुआ है। यह केवल याचिकाकर्ताओं का स्व-मूल्यांकन है कि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया होता, तो वे मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए होते। केवल इस आशय के बयान के आधार पर, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार पक्षकारों के अधिवक्ता को विस्तार से सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों की अत्यधिक सावधानी से जाँच करने के बाद, यह न्यायालय इस अकाट्य निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एक छात्र जो योग्यता के आधार पर चुने जाने का हकदार है, भले ही वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित हो, वह अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तदनुसार, उपरोक्त सुस्थापित विधिक स्थिति के आलोक में, याचिकाकर्ताओं का कोई मामला स्वीकार्य नहीं है और याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

16. परिणामस्वरूप, याचिकाएं विफल होती हैं और तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है।

सही/-

प्रीतीन्कर दीवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by ---- Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur